पहले भूमिपूजन में छह लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारेगी सरकार

प्रदेश में निवेश के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही का दिया गया लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 में हुए 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश करार में से पहले भूमिपूजन समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) में पांच से छह लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतारे जाएंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) मनोज कुमार सिंह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 28 विभागों को दस लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं की स्वीकृति और भूमि आवंटन की कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार के 28 प्रमुख विभागों व संस्थाओं में कुल 31,37,282 करोड़ रुपये के निवेश करार हुए हैं, जबकि शेष अन्य विभागों से। शासन स्तर पर आगामी छह महीने में प्रथम चरण में 5-6 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मौके पर शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने का निर्णय किया गया है। आयुक्त ने 5-6 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए प्राप्त करार की स्वीकृति और भूमि आवंटन की कार्यवाही का निर्देश दिया है। आयुक्त ने इसके लिए विभागवार लक्ष्य भी तय कर दिए हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया गया है। जबकि नवीनीकृत ऊर्जा विभाग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नगरीय विकास और आवास विभाग को एक-एक लाख करोड़ की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का लक्ष्य दिया गया है।

विभाग	कुल निवेश	जीबीसी का लक्ष्य
उप्र. औद्योगिक विकास प्राधिकरण	3,15,507	1,60,000
नवीनीकृत ऊर्जा विभाग	6,33,344	1,00,000
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	4,73,160	1,00,000
नगरीय विकास विभाग	2,07,424	1,00,000
आवास विभाग	150251	80,000
नोएडा अथॉरिटी	88,697	60,000
एमएसएमई	1,37,555	50,000
उच्च शिक्षा	2,59,026	50,000
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी	74,053	40,000
उद्यानिकी विभाग	51,802	35,000
यमुना अथॉरिटी	1,10,119	35,000
ऊर्जा विभाग	1,34,257	30,000
पर्यटन विभाग	1,29,489	30,000
कपड़ा एवं वस्त्रोद्योग	55,999	25,000
यूपीडा	32109	15,000
खाद्य एवं रसद आपूर्ति	32,216	10,000
गीडा	18,257	10,000

करोड़ रुपये में